



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2021 ई0 (कार्तिक 29, 1943 शक सम्वत्) [संख्या-47

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	3075
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	581-598	1500
भाग 1-क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	769-783	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	405-406	975
स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5

अधिसूचना

प्रकीर्ण

25 अक्टूबर, 2021 ई0

संख्या:-971/XXVIII(5)/2021/10(सामान्य)/2020-राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न संवर्ग में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (राजकीय मेडिकल कॉलेज) विभिन्न संवर्ग

सेवा नियमावली, 2021

भाग-एक-सामान्य

- | | |
|---------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (राजकीय मेडिकल कॉलेज) विभिन्न संवर्ग सेवा नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| सेवा की प्रास्थिति | 2. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (राजकीय मेडिकल कॉलेज) विभिन्न संवर्ग सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह 'ख' एवं 'ग' श्रेणी के पद समाविष्ट हैं। |
| परिभाषाएं | 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-
(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है ;
(ख) 'बोर्ड' से 'उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड' अभिप्रेत है ;
(ग) 'भारत का नागरिक' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो "भारत का संविधान" के भाग-II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय ;
(घ) "संविधान" से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है ;
(ङ) "निदेशक" से 'निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड राज्य' अभिप्रेत है ;
(च) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है ;
(छ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ;
(ज) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;
(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ;
(ञ) "भर्ती का वर्ष" से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है। |

भाग 2—संवर्गसेवा का
संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।
- (2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट-क में दी गयी है :

परन्तु यह कि :-

- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- (दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

भाग 3—भर्तीभर्ती का
स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नानुसार की जायेगी :-

क्र०सं०	पद	भर्ती का स्रोत
1	हेल्थ इंस्पेक्टर/ हेल्थ असिस्टेंट(पुरुष)	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
2	हेल्थ एजुकेटर	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
3	डिजीज, हेल्थ विजिटर	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
4	स्पीच थेरेपिस्ट	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
5	चाईल्ड साइकोलॉजिस्ट	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
6	वैकेशनल काउन्सलर	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
7	प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थोटिक टैक्नीशियन	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
8	क्लीनिकल साइकलॉजिस्ट	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
9	मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
10	डी०एच० अटेंडेन्ट	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
11	फोटोग्राफर	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
12	आर्टिस्ट/माडलर	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
13	ऑडियोविजुअल टैक्नीशियन	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
14	डाइटेरियन	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
15	स्टेडिस्टिशियन	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
16	सीनियर टैक्नीशियन	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
17	जूनियर टैक्नीशियन	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
18	मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग 4—अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—
- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से, 01 जनवरी, 1962 के

पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि, श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप पुलिस उप महानिदेशक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, तो प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक
अर्हता

8. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिए :-

क्र० सं०	पद	अर्हता
1.	हैल्थ इंस्पेक्टर/हैल्थ असिस्टेंट(मेल)	- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा के साथ हैल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर का 01 वर्षीय कोर्स डिप्लोमा तथा 200 शैय्याओं वाले चिकित्सालय में 04 वर्ष का कार्यानुभव।
2.	हैल्थ एजुकेटर	- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी में एम0ए0/एम0एस0सी0 के साथ किसी रिहबिलिटेशन सेन्टर में 05 वर्ष का कार्यानुभव।
3.	डिजीज विजिटर (टी0बी0एण्ड चेस्ट)	- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी0एस0सी0 (नर्सिंग) या नर्सिंग में डिप्लोमा के साथ सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का कार्यानुभव।
4.	स्पीच थेरेपिस्ट	- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से Speech and Hearing में बी.एस.सी. की डिग्री।
5.	चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट	- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी में एम.ए./एम.एस.सी. के साथ क्लीनिकल साइकोलॉजी में एम.फिल० तथा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त सरकारी या अर्धसरकारी संस्थान से 02 वर्ष का कार्यानुभव।
6.	वोकेशनल काउन्सलर	- i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि। ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में वोकेशनल काउन्सलिंग (Vocational Guidance) में पी0जी0 डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त किया हो। iii) सम्बन्धित क्षेत्र में 05 वर्ष का कार्यानुभव।

7. प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थोटिक टैक्नीशियन - i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से प्रोस्थेटिक्स एण्ड आर्थोटिक्स में स्नातक की उपाधि।
ii) रिहैबिलिटेशन काउन्सिल में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
8. मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर - i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से फिजियोथिरेपी में स्नातक की उपाधि के साथ 02 वर्ष का कार्यानुभव या रिहैबिलिटेशन में डिप्लोमा के साथ 05 वर्ष का कार्यानुभव।
ii) फिजियोथिरेपी काउन्सिल में पंजीकरण होना अनिवार्य।
9. क्लीनिकल साइक्लॉजिस्ट - किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी में एम.ए./एम.एस.सी. के साथ क्लीनिकल साइकोलॉजी में एम.फिल0 तथा क्लीनिकल साइक्लॉजिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त सरकारी या अधिसरकारी संस्थान से 02 वर्ष का कार्यानुभव।
10. डी0एच0 अटेन्डेन्ट - इण्टरमीडिएट परीक्षा के साथ सम्बन्धित क्षेत्र में 01 वर्ष का कार्यानुभव।
या
हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण के साथ 03 वर्ष का सम्बन्धित क्षेत्र में कार्यानुभव।
11. फोटोग्राफर - i) इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वाणिज्यिक या ग्राफिय कला में डिप्लोमा।
iii) किसी सरकारी या अधिसरकारी संस्था में 01 वर्ष का कार्यानुभव।
12. आर्टिस्ट/माडलर - किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फाइन-आर्ट या कॉमर्शियल आर्ट में डिप्लोमा/स्टीफिकेट कोर्स के साथ 02 वर्ष का कार्यानुभव।
13. ऑडियोविजुअल टैक्नीशियन - 10+2 के साथ किसी राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से सर्टिफिकेट कोर्स/समकक्ष डिग्री और डिप्लोमा।
14. डाइटीशियन - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.एस.सी.(होम साइंस और न्यूट्रेशन)/एम.एस.सी. (क्लीनिकल न्यूट्रेशन और डाइटेटिक्स)/एम.एस.सी. (फूड साइन्स एण्ड न्यूट्रेशन)/एम.एस.सी. (फूड एण्ड न्यूट्रेशन डाइटेटिक्स)/एम.एस.सी. (फूड सर्विस मैनेजमेन्ट एण्ड डाइटेटिक्स) के साथ 03 वर्ष का कार्यानुभव।
15. स्टेटिस्टिशियन - किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0एस0सी0 स्टेटिक्स/ एम0एस0सी0 बायो स्टेटिक्स के साथ 02 वर्ष का कार्यानुभव।
16. सीनियर टैक्नीशियन (इलेक्ट्रीकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रानिक एवं रेफ्रिजेशन) - किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्नीक से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रानिक्स, रेफ्रिजेशन में तीन वर्षीय डिप्लोमा के साथ 02 वर्ष का कार्यानुभव।

17. जूनियर टैक्नीशियन - किसी मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से इलेक्ट्रिकल, (इलैक्ट्रीकल, इलैक्ट्रानिक) इलैक्ट्रानिक्स में प्रशिक्षण के साथ 02 वर्ष का कार्यानुभव।
18. मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर - किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मेडिकल रिकॉर्ड में एक वर्षीय डिप्लोमा/कोर्स तथा किसी राजकीय चिकित्सालय में सम्बन्धित कार्यों का 05 वर्ष का कार्यानुभव।

टिप्पणी:-इस नियमावली के प्रख्यापित होने से पूर्व उत्तराखण्ड के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेजों में यदि कोई कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हो तो उनके लिए शैक्षिक अर्हता वही मान्य होगी, जो उसकी नियुक्ति के समय निर्धारित थी या विज्ञापित की गयी थी। अन्य सभी सेवा लाभ नियमावली के अनुसार देय होंगे।

- अनिवार्य अर्हता** 9. अनिवार्य अर्हता- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) निहित शर्तों/उपबन्धों के अनुसार होगी।
- अधिमानी अर्हता** 10. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने -
(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
(ख) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
- आयु** 11. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाती हैं, उस वर्ष की पहली जुलाई को उतनी न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु प्राप्त ना की हो जैसा समय-समय पर निर्धारित की जाय ;
परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
- चरित्र** 12. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

- वैवाहिक प्रास्थिति** 13. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसके एक से अधिक जीवित पति हों,
परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।
- शारीरिक स्वस्थता** 14. किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे वितीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के

अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016 भारत सरकार) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग 5-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और बोर्ड को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 (समय-समय पर यथासंशोधित) के उपबन्धों के अनुसार उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निम्नानुसार की जायेगी:-

(एक) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो विज्ञापन जारी करके,
(दो) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(2) चयन समिति नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेगी।

(3)(एक) लिखित परीक्षा 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा तथा विषय से सम्बन्धित 100 अंकों का दूसरा प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(दो) लिखित परीक्षा के प्रश्न, बुकलेट, परीक्षा के पश्चात, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी।

(तीन) लिखित परीक्षा के पश्चात्, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.ua.nic.in पर या दैनिक समाचार पत्र जिसका व्यापक परिचालन हो में प्रकाशित किया जाएगा।

(चार) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी।

(पांच) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) के उपबन्धों के अनुसार होगी।

(4) चयन समिति/बोर्ड प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांकों से प्रकट प्रवीणता (श्रेष्ठता/वरियता) के क्रम में एक संयुक्त चयन सूची तथा आरक्षित वर्ग की पृथक-पृथक चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी तथा नियुक्ति के लिये उतने ही

अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगी जिन्हें वे योग्य समझती है। यदि दो या उनसे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। चयन समिति/बोर्ड द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

भाग 6-नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

- नियुक्ति** 17. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें उनके नाम यथा स्थिति नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्ति करेगा।
(2) यदि किसी चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर उस क्रम में यथास्थिति जिस क्रम में उसका नाम उस संवर्ग में है।
- परीक्षा** 18. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को 02 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक-पृथक मामले में परीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय :
परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।
(3) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
(4) ऐसे परीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के सम्बन्ध में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न या स्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकेगा।
- स्थायीकरण** 19. परीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि -
(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित कर दी जाये; और
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।
- ज्येष्ठता** 20. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर किसी कर्मचारी की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

भाग 7-वेतन

- वेतनमान** 21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त कार्मिक को अनुमन्य वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ में प्रचलित वेतनमान परिशिष्ट-‘क’ में दिये गये हैं।
- परिवीक्षा के दौरान वेतन** 22. (1) मूल नियम में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन कर्मचारी को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रथम वेतन वृद्धि प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि 02 वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी।
- परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।
- (2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :
- परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।
- (3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग-8-अन्य उपबन्ध

- पक्ष समर्थन** 23. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित शिफारिशों से भिन्न किन्हीं शिफारिशों पर, चाहें लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अन्यर्था की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।
- अन्य विषयों का विनियमन** 24. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।
- सेवा शर्तों का शिथिलीकरण** 25. जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम के अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रिक्ति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :
- परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

ध्यावृत्ति

26. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट-क

(नियत 4(2) एवं 21(2) देखें)

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	राजकीय मेडिकल कॉलेज				कुल योग
			श्रीनगर	हल्द्वानी	देहरादून	अल्मोड़ा	
1	हेल्थ इंस्पेक्टर/हेल्थ असिस्टेंट(मेल)	29200-92300 (लेवल-5)	03	03	03	03	12
2	हेल्थ एजुकेटर	29200-92300 (लेवल-5)	02	02	02	02	08
3	डिजीज, हेल्थ विजिटर (टी0बी0एण्ड चेस्ट)	29200-92300 (लेवल-5)	02	02	02	02	08
4	स्पीच थेरेपिस्ट	29200-92300 (लेवल-5)	02	02	02	02	08
5	चाईल्ड साइकोलॉजिस्ट	35400-112400 (लेवल-6)	01	01	01	01	04
6	मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर	29200-92300 (लेवल 5)	04	04	04	04	16
7	वोकेशनल काउन्सलर	35400-112400 (लेवल-6)	01	01	01	01	04
8	प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थोटिक टैक्नीशियन	21700-69100 (लेवल-3)	02	02	02	02	08
9	क्लीनिकल साइकलॉजिस्ट	35400-112400 (लेवल-6)	01	01	01	01	04
10	डी0एच0 अटेन्डेन्ट	19900-63200 (लेवल-2)	04	04	04	04	16
11	फोटोग्राफर	19900-63200 (लेवल-2)	01	01	01	01	04
12	आर्टिस्ट/माडलर	19900-63200 (लेवल-2)	02	02	02	02	08
13	ऑडियोविजुअल टैक्नीशियन	25500-81100 (लेवल-4)	03	03	03	03	12
14	डाइटीशियन	29200-92300 (लेवल 5)	01	01	01	01	04
15	स्टेटिस्टिशियन	29200-92300 (लेवल 5)	01	01	01	01	04
16	सीनियर टैक्नीशियन	29200-92300 (लेवल 5)	04	04	04	04	16
17	जूनियर टैक्नीशियन	25500-81100 (लेवल-4)	02	02	02	02	08
18	मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर	56100-177500 (लेवल-10)	01	01	01	01	04

अधिसूचना

प्रकीर्ण

25 अक्टूबर, 2021 ई0

संख्या:—973/XXVIII(5)/2021-18(सामान्य)/2020—राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग की लाइब्रेरी संवर्ग सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग लाइब्रेरी (लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन असिस्टेंट(डाक्यूमेंटलिस्ट/कैटालॉगर) संवर्ग सेवा नियमावली, 2021

भाग—एक—सामान्य

- | | |
|---------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. (1) इस नियमावली, का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग लाइब्रेरी (लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन असिस्टेंट (डाक्यूमेंटलिस्ट/कैटालॉगर) संवर्ग सेवा नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| सेवा की प्राप्ति | 2. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग लाइब्रेरी (लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन असिस्टेंट (डाक्यूमेंटलिस्ट/कैटालॉगर) संवर्ग सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ख' व 'ग' के पद समाविष्ट है। |
| परिभाषाएं | 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—
(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
(ख) 'बोर्ड' से 'चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, उत्तराखण्ड' अभिप्रेत है;
(ग) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग-II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय ;
(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;
(ङ) 'निदेशक' से 'निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड राज्य' अभिप्रेत है;
(च) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(छ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(ज) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(झ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग लाइब्रेरी (लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन असिस्टेंट (डाक्यूमेंटलिस्ट/कैटालॉगर) सेवा अभिप्रेत है;
(ञ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो; |

(ट) 'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2—संवर्ग

- सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।
(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट-क में दी गयी है :

परन्तु यह कि —

- (एक). नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

भाग 3—भर्ती

- भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नानुसार की जायेगी :—

1- लाइब्रेरियन असिस्टेंट (डाक्यूमेंटालिस्ट/कैटालॉगर):- सीधी भर्ती।

2- डिप्टी लाइब्रेरियन :-शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन (डाक्यूमेंटालिस्ट/कैटालॉगर) जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से।

3- लाइब्रेरियन :-शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे डिप्टी लाइब्रेरियन जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भर्ती के समय पर यथोचित अधिसूचित-शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण सम्बन्धित पदों पर भर्ती के समय उत्तराखण्ड राज्य में लागू आरक्षण नीति के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4—अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—
(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया

गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी भी पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी: जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता 8. सेवा में लाइब्रेरियन असिस्टेंट (डाक्यूमेंटालिस्ट/कैटालॉगर) पर सीधी भर्ती के लिए अर्हता निम्नानुसार होगी:-

लाइब्रेरियन असिस्टेंट (डाक्यूमेंटालिस्ट/कैटालॉगर) - किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि के साथ लाइब्रेरी साइंस में डिग्री।

टिप्पणी:- इस नियमावली के प्रख्यापित होने से पूर्व उत्तराखण्ड के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेजों में यदि कोई कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हो तो उनके लिए शैक्षिक अर्हता वही मान्य होगी, जो उसकी नियुक्ति के समय निर्धारित थी या विज्ञापित की गयी थी। अन्य सभी सेवा लाभ नियमावली के अनुसार देय होंगे।

अनिवार्य अर्हता 9. अनिवार्य योग्यता उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित शर्तों/उपबन्धों के अनुसार होगी।

अधिमानी अर्हता 10. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामलों में अधिमान दिया जायेगा, जिसने -

- (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या
- (2) नेशनल कैडेट्स कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु 11. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाती हैं, उस वर्ष की पहली जुलाई को उतनी न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु प्राप्त न की हो, जैसा समय-समय पर निर्धारित की जाय ;

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी जितनी बिनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

12. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक
प्रास्थिति

13. ऐसा पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसका एक से अधिक जीवित पति हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र न होंगे :

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक
स्वस्थता

14. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग तीन के अध्याय-तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम सं0 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग 5-भर्ती की प्रक्रियारिक्तियों की
अवधारणा

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर व अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवा योजन कार्यालय/चयन आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की
प्रक्रिया

16. सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली 2008 के एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित नियमावलियों के उपबन्धों के अनुसार इस नियमावली के नियम 8 में दी गयी निर्धारित शैक्षिक योग्यता के आधार पर उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से निम्नानुसार की जायेगी:-

(एक) ऐसे न्यूनतम दैनिक समाचार पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो विज्ञापन जारी करके,

(दो) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।

- (1) चयन समिति नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व को ध्यान रखते हुए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेगी।
- (2)(एक) लिखित परीक्षा 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा तथा विषय से सम्बन्धित दूसरा प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु $1/4$ ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।
- (दो) लिखित परीक्षा के प्रश्न, बुकलेट, परीक्षा के पश्चात, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी।
- (तीन) लिखित परीक्षा के पश्चात, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.ua.nic.in पर या दैनिक समाचार पत्र में जिसका व्यापक परिचालन है, प्रकाशित किया जाएगा।
- (चार) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी।
- (पांच) लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अनुपयुक्त होंगे।
- (3) चयन समिति/आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों से प्रकट प्रवीणता (श्रेष्ठता/वरियता) के क्रम में एक चयन सूची तथा आरक्षित वर्ग की पृथक-पृथक चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा तथा नियुक्ति के लिये उतने ही अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगी जिन्हें वे योग्य समझती है। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हो तो, आयु में अधिक अभ्यर्थी को सूची में उपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची 01 वर्ष के लिए मान्य होगी। समिति सूची से अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों के नाम योग्यता के क्रम में नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

पदोन्नति के लिए प्रक्रिया

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिये) नियमावली 2002 समय-समय पर यथासंशोधित के उपबन्धों के अधीन गठित चयन समिति द्वारा नियम 5 के आधार पर की जायेगी।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जाय।
- (3) चयन समिति द्वारा उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।
- (4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

संयुक्त चयन 18. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत

सूची

सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग 6—नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता**नियुक्ति**

19. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 16, 17 तथा 18 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।
- (2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी तब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 18 के अनुसार संयुक्त चयन सूची तैयार न की गयी हों।
- (3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्रियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहाँ पद उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के विनियम 5 (क) के प्रावधान लागू होंगे।

परीक्षा

20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को 02 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक-पृथक मामले में परीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय :
- परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।
- (3) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
- (4) ऐसे परीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

- (5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के सम्बन्ध में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य किसी अन्य समकक्ष या किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न या स्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकेगा।
- स्थायीकरण** 21. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि—
- (क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो।
 (ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है तथा
 (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।
- ज्येष्ठता** 22. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर नियुक्त किसी कर्मचारी की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार किया जायेगा।

भाग 7—वेतन

- वेतनमान** 23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त कार्मिक को अनुमन्य वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ में प्रचलित वेतनमान परिशिष्ट-क में दिये गये हैं। इस नियमावली प्रख्यापित होने के बाद यदि वेतनमानों में कोई संशोधन होता है, तो परिशिष्ट-क में दिये गये वेतनमान स्वतः संशोधित माने जायेंगे।
- परिवीक्षा के दौरान वेतन** 24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन कर्मचारी को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रथम वेतन वृद्धि प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि 02 वर्ष की सेवा के पश्चात परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी :
- परन्तु यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।
- (2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :
- परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।
- (3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग-8-अन्य उपबन्ध

- पक्ष समर्थन** 25. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहें लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।
- अन्य विषयों का विनियमन** 26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।
- सेवा शर्तों का शिथिलीकरण** 27. जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम के अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :
परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।
- व्यावृत्ति** 28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट-क

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान (₹)	राजकीय मेडिकल कॉलेज				कुल योग
			श्रीनगर	हल्द्वानी	देहरादून	अल्मोड़ा	
1	लाइब्रेरियन	56100-177500 (लेवल 10)	01	01	01	01	04
2	डिप्टी लाइब्रेरियन	35400-112400 (लेवल 6)	01	01	01	01	04
3	लाइब्रेरियन असिस्टेंट (डाक्यूमेंटलिस्ट/ कैटालॉगर)	25500-81100 (लेवल 4)	06	06	06	06	24

आज्ञा से,

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 47 हिन्दी गजट/439-भाग-1-2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2021 ई० (कार्तिक 29, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, PITHORAGARH

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

July 24, 2021

Endorsement No. 449(07)/I-10-2020-- Certified that the Office of the District & Sessions Judge, Pithoragarh was handed over on proceeding to medical leave w.e.f. 14-07-2021 to 23-07-2021 in anticipation of sanction of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital, as hereinafter denoted, in the forenoon of July 14, 2021.

Dr. GYANENDRA KUMAR SHARMA,

District & Sessions Judge,

Pithoragarh.

Counter-signed,

illegible,

Registrar General,

Hon'ble High Court of Uttarakhand,

Nainital.

CERTIFICATE OF TAKEN OVER CHARGE

July 24, 2021

Endorsement No. 450(07)/I-10-2020--Certified that the Office of the District & Sessions Judge, Pithoragarh was taken over after availing medical leave w.e.f. 14-07-2021 to 23-07-2021 in anticipation of sanction of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital, as hereinafter denoted, in the forenoon of July 24, 2021.

Dr. GYANENDRA KUMAR SHARMA,
District & Sessions Judge,
Pithoragarh.

Counter-signed,
illegible,
Registrar General,
Hon'ble High Court of Uttarakhand,
Nainital.

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNALCHARGE CERTIFICATE

September 01, 2021

No. 182/PST/Admin.IV/2021/D.Dun--Certified that in compliance of the Hon'ble High Court of Uttarakhand Letter No. 3940/XVII-62/Admin.A/2004, Dated 11.08.2021 and vide Uttarakhand Government Nyay Anubhag-I Notification No.317(3)XXXVI-A-1/2021-18/2001 T.C.-I, Dated 25.08.2021, the charge of the office of the Registrar, Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun has been taken over, as denoted herein, in the afternoon of 01.09.2021.

MAHESH CHANDRA KAUSHIWA,
Relieving Officer.

Countersigned,
illegible,
Chairman,
Uttarakhand Public Services Tribunal,
Dehradun.

LEGISLATIVE & PARLIAM ENTARY AFFAIRS,
GOVT. OF UTTARAKHAND

CHARGE CERTIFICATE

September 27, 2021

No. 274/XXXVI(3)/2021--Certified that in compliance of Letter No. 4672/XIII-f-1/Admin.A/2008 Dated September 24, 2021 of the Hon'ble High Court of Uttarakhand and D.O. Letter No. 561/XXX-1-2021 dated 23.09.2021 of the Secretary, Personnel & Vigilance, Govt. of Uttarakhand, Dehradun, the charge of the office of the Additional Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs, Govt. of Uttarakhand, Dehradun has been taken over, as denoted herein, in the afternoon of 27.09.2021.

MAHESH CHANDRA KAUSHIWA,

Relieving Officer.

Countersigned,

HIRA SINGH BONAL,

Principal Secretary,

Legislative & Parliamentary Affairs,

Govt. of Uttarakhand.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

11th October, 2021

No. 341/UHC/Admin.A/2021--Hon'ble Shri Justice Sanjaya Kumar Mishra, Judge of the Orissa High Court has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Uttarakhand, Nainital on 11.10.2021 at 11:50 A.M. pursuant to Notification No. K.11019/39/2021-US.I/II (iii) dated 05.10.2021 issued by Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice (Appointments Division), Jaisalmer House, 26, Man Singh Road, New Delhi.

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

NOTIFICATION

October 20, 2021

No. 344/UHC/Admin.A/2021--In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India, High Court of Uttarakhand with the approval of the Governor, hereby makes the following Rules for regulating the procedure and practice in the Criminal Courts, subordinate to the High Court:-

THE UTTARAKHAND CRIMINAL COURTS PROCEDURE AND PRACTICE RULES, 2021

PART I : PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement-** (1) These rules shall be called The Uttarakhand Criminal Courts Procedure and Practice Rules, 2021.
 - (2) These rules shall apply to all proceedings and matters in all Criminal Courts subordinate to the High Court.
 - (3) They shall come into force at once.
2. **Interpretation-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires-
 - (a) 'Code' means the Code of Criminal Procedure, 1973.
 - (b) 'Court' means any Criminal Court established under the Code, any special law or any local law, time being in force.
 - (c) 'Existing rules' mean all rules, including the General Rules (Criminal), 1977 regulating the procedure and practice in the Courts.
 - (d) 'High Court' means the High Court of Uttarakhand.
 - (e) 'Presiding Officer' means Presiding Officer of the Court.
 - (f) 'Rules' mean the Uttarakhand Criminal Courts Procedure and Practice Rules, 2021
 - (g) 'Sessions case' means a case triable by Court of Sessions.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Code, shall have the meanings respectively assigned to them in that Code.

PART II : SUPPLY OF DOCUMENTS

3. Every Accused shall be supplied with statements of witness recorded under Sections 161 and 164 of the Code and a list of documents, material objects and exhibits seized during investigation and relied upon by the Investigating Officer (I.O) in accordance with Sections 207 and 208 of the Code.

Explanation: The list of statements, documents, material objects and exhibits shall specify statements, documents, material objects and exhibits that are not relied upon by the Investigating Officer.

PART III : CHARGE

4. The order framing charge shall be accompanied by a formal charge in Form 32, Schedule II of the Code to be prepared personally by the Presiding Officer after complete and total application of mind.

PART IV : TRIAL**CHAPTER 1****RECORDING OF EVIDENCE : PROCEDURE**

5. The depositions of witnesses shall be recorded, in typed format, if possible. The record of evidence shall be prepared on computers, if available, in the Court on the dictation of the Presiding Officer :

Provided that in case the language of deposition is to be recorded in a language other than English or the language of the State, the Presiding Officer shall simultaneously translate the deposition either himself or through a competent translator into English.

6. The deposition shall be recorded in the language of the witness and in English when translated as provided in rule 5.
7. The depositions shall without exception be read over by the Presiding Officer in Court. Hard copy of the testimony so recorded duly signed to be a true copy by the Presiding Officer or the Reader of the Court, shall be made available free of cost against receipt to the accused or the advocate representing the accused, to the witness and the prosecutor on the date of recording.
8. A translator shall be made available in each Court and Presiding Officers shall be trained in the local languages, on the request of the Presiding Officer.
9. The Presiding Officers shall not record evidence in more than one case at the same time.

CHAPTER 2**RECORDING OF EVIDENCE : FORMAT OF WITNESSES**

10. The deposition of each witness shall be recorded dividing it into separate paragraphs assigning paragraph numbers.
11. Prosecution witnesses shall be numbered as PW-1, PW-2 etc, in *seriatim*. Similarly, defence witnesses shall be numbered as DW-1, DW-2, etc., in *seriatim*. The Court witnesses shall be numbered as CW-1, CW-2, etc, in *seriatim*.

12. The record of depositions shall indicate the date of the examination-in-chief, the cross examination and re-examination.
13. The Presiding Officers, shall, wherever necessary, record the deposition in question and answer format.
14. Objections by either the prosecution or the defence counsel shall be taken note of and reflected in the evidence and decided immediately, in accordance with law, or, at the discretion of the Presiding Officer, at the end of the deposition of the witness in question.
15. The name and number of the witness shall be clearly stated on any subsequent date, if the evidence is not concluded on the date on which it begins.

CHAPTER 3

EXHIBITING OF MATERIAL OBJECTS AND EVIDENCE

16. Prosecution exhibits shall be marked as Exhibit P-1, P-2 etc in *seriatim*. Similarly, defence Exhibits shall be marked as Exhibit D-1, D-2, etc in *seriatim*. The Court exhibit shall be marked as Exhibit C-1, C-2, etc in *seriatim*.
17. To easily locate the witness through whom the document was first introduced in evidence, the exhibit number shall further show the witness number of such witness after the Exhibit number. If an exhibit is marked without proper proof, the same shall be indicated by showing in brackets (subject to proof).
Explanation: If Prosecution witness No. 1 (PW1) introduces a document in evidence, that document shall be marked as Exhibit P-1/PW1. If proper proof is not offered for that document at the time when it is marked, it shall be marked as Exhibit P-1/PW1 (subject to proof). The Second document introduced by PW1 will be Exhibit P-2/PW1.
18. The Material objects shall be marked in *seriatim* as MO-1, MO-2 etc.

CHAPTER 4

SUBSEQUENT REFERENCES TO ACCUSED, WITNESS, EXHIBITS AND MATERIAL OBJECTS

19. After framing of charges, the accused shall be referred to only by their ranks in the array of accused in the charge and not by their names or other references except at the stage of identification by the witness.

20. After recording the deposition of witnesses, marking of the exhibits and material objects, while recording deposition of other witnesses, the witnesses, exhibits and material objects shall be referred by their numbers and not by names or other references.
21. Where witness cited in the complaint or police report are not examined, they shall be referred to by their names and the numbers allotted to them in the complaint or police report.

CHAPTER 5
REFERENCES TO STATEMENTS UNDER
SECTION 161 AND 164 OF THE CODE

22. During cross examination, the relevant portion of the statements recorded under Section 161 of the Code used for contradicting the respective witness shall be extracted. If it is not possible to extract the relevant part as aforesaid, the Presiding Officer, in his discretion, shall indicate specifically the opening and closing words of such relevant portion, while recording the deposition, through distinct marking.
23. In such cases, where the relevant portion is not extracted, the portions only shall be distinctly marked as prosecution or defence exhibit as the case may be, so that other inadmissible portions of the evidence are not part of the record.
24. In cases, where the relevant portion is not extracted, the admissible portion shall be distinctly marked as prosecution or defence exhibit as the case may be.
25. The aforesaid rule applicable to recording of the statements under Section 161 shall *mutatis mutandis* apply to statements recorded under Section 164 of the Code, whenever such portions of prior statements of living persons are used for contradiction/corroboation.
26. Omnibus marking of the entire statement Under Section 161 and 164 of the Code shall not be done.

CHAPTER 6
MARKING OF CONFESSIONAL STATEMENTS

27. The Presiding Officers shall ensure that only admissible portion of Section 8 or Section 27 Indian Evidence Act, 1872 is marked and such portion alone is extracted on a separate sheet and marked and given an exhibit number.

PART V : THE JUDGMENT

28. Every judgement shall contain the following
- (A) Start with a preface showing the names of parties as per FORM A to the Rules.
 - (B) A tabular statement as per FORM B to the Rules.
 - (C) An appendix giving the list of prosecution witnesses, defence witnesses, Court witnesses, Prosecution Exhibits, Defence Exhibits and Court Exhibits and Material Objects as per FORM C to the Rules.
29. In compliance with Section 354 and 355 of the Code, in all cases, the judgments shall contain:
- (A) the point or points for determination,
 - (B) the decision thereon, and
 - (C) the reasons for the decision
30. In case of conviction, the judgment shall separately indicate the offence involved and the sentence awarded. In case there are multiple accused, each of them shall be dealt with separately. In case of acquittal and if the accused is in confinement, a direction shall be given to set the accused at liberty, unless such accused is in custody in any other case.
31. In the judgment, the accused, witnesses, exhibits and material objects shall be referred to by their nomenclature or number and not only by their names or otherwise. Wherever, there is a need to refer to the accused or witnesses by their name, the number shall be indicated within brackets.
32. The judgment shall be written in paragraphs and each paragraph shall be numbered in *seriatim*. The Presiding Officers, may, in their discretion, organize the judgment into different sections.

PART VI : BAIL

33. The application for bail in non-bailable cases must ordinarily be disposed of within a period of 3 to 7 days from the date of first hearing. If the application is not disposed of within such period, the Presiding Officer shall furnish reasons thereof in the order itself. Copy of the order and the reply to the bail application or status report (by the police or prosecution) if any, shall be furnished to the accused and to the accused on the date of pronouncement of the order itself.
34. The Presiding Officer may, in an appropriate case in its discretion insist on a statement to be filed by the prosecutor in charge of the case.

PART VII : DIRECTIONS FOR EXPEDITIOUS TRIAL

35. In every enquiry or trial, the proceedings shall be held as expeditiously as possible, and, in particular, when the examination of witnesses has once begun, the same shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded.

Note: Please see sub-section (1) of Section 309 of the Code.

36. For the aforesaid purpose, at the commencement, and immediately after framing charge, the court shall hold a scheduling hearing, to ascertain and fix consecutive dates for recording of evidence, regard being had to whether the witnesses are material, or eye witnesses, or formal witnesses or are experts.
37. The court then shall draw up a schedule indicating the consecutive dates, when witnesses would be examined; it is open to schedule recording of a set of witnesses depositions on one date, and on the next date, other sets, and so on. The court shall also, before commencement of trial, ascertain if the parties wish to carry out admission of any document under Section 294, and permit them to do so, after which such consecutive dates for trial shall be fixed.

38. After the commencement of the trial, if the court finds it necessary or advisable to postpone the commencement of, or adjourn, any inquiry or trial, it may, from time to time, for reasons to be recorded postpone or adjourn the same on such terms as it thinks fit, for such time as it considers reasonable. If witnesses are in attendance, no adjournment or postponement shall be granted, without examining them, except for special reasons to be recorded, in writing.

Note: Please see sub-section (2) of Section 309 of the Code.

39. Sessions cases may be given precedence over all other work and no other work should be taken up on sessions days until the sessions work for the day is completed. A Sessions case once posted should not be postponed unless that is unavoidable, and once the trial has begun, it should proceed continuously from day to day till it is completed. If for any reason, a case has to be adjourned or postponed, intimation should be given forthwith to both sides and immediate steps be taken to stop the witnesses and secure their presence on the adjourned date.

PART VIII: AMENDMENTS IN EXISTING RULES

40. All existing rules, notifications, orders, practice and directions on the subject, which are covered under these rules, shall stand amended to the extent that these rules shall only apply.
41. All existing rules, notifications, orders, practice and directions on the subject, which are not covered under these rules shall remain unaffected and shall continue apply.

FORM A

IN THE COURT OF

Present: Sessions Judge

[Date of the Judgement]

[Case No...../20...]

(Details of FIR/Crime and Police Station)

Complainant	STATE OF..... OR NAME OF THE COMPLAINANT
REPRESENTED BY	NAME OF THE ADVOCATE
ACCUSED	1. NAME WITH ALL PARTICULARS (A1) 2. NAME WITH ALL PARTICULARS (A2)
REPRESENTED BY	NAME OF THE ADVOCATES

FORM B

Date of Offence	
Date of FIR	
Date of Chargesheet	
Date of Framing of Charges	
Date of commencement of evidence	
Date on which judgment is reserved	
Date of the Judgment	
Date of the Sentencing Order, if any	

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428 of Cr.PC

FORM C**LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES****A. Prosecution**

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
PW1		
PW2		

B. Defence Witnesses, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
DW1		
DW2		

C. Court Witnesses, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
CW1		
CW2		

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS**A. Prosecution:**

SL. No	Exhibit Number	Description
1	Exhibit P-1/PW1	
2	Exhibit P-2/PW2	

B. Defence:

SL. No	Exhibit Number	Description
1	Exhibit D-1/DW1	
2	Exhibit D-2/DW2	

C. Court Exhibits

SL. No	Exhibit Number	Description
1	Exhibit C-1/CW1	
2	Exhibit C-2/CW2	

D. Material Objects:

SL. No	Material Object Number	Description
1	MO1	
2	MO2	

By Order of the Court,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

NOTIFICATION

October 23, 2021

No. 349/XIV/a-39/Admin.A/2017--Ms. Shalini Dadar, Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned child care leave of 31 days w.e.f. 01.09.2021 to 01.10.2021 with permission to suffix 02.10.2021 as Mahatma Gandhi Jyanati & 03.10.2021 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

October 26, 2021

No. 351/XIV-28/Admin.A/2008-Shri Sudhir Tomar, Chief Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 22 days w.e.f. 17.09.2021 to 08.10.2021.

NOTIFICATION

October 29, 2021

No. 352/XIV/14/Admin.A/2008--Shri Dharmendra Kumar Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 22.09.2021 to 01.10.2021 with permission to suffix 02.10.2021 as Mahatma Gandhi Jayanti & 03.10.2021 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

October 29, 2021

No. 354/XIV-a-10/Admin.A/2009--Ms. Gunjan Singh, Additional Judge, Family Court Roorkee, District Haridwar, is hereby sanctioned child care leave for 19 days w.e.f. 20.09.2021 to 08.10.2021.

NOTIFICATION

October 29, 2021

No. 355/XIV-a/28/Admin.A/2012--Ms. Ritika Semwal, Civil Judge (Sr. Div.), Tehri Garhwal, is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 27.09.2021 to 16.10.2021 with permission to prefix 26.09.2021 and suffix 17.10.2021 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

October 29, 2021

No. 356/XIV-a-41/Admin.A/2013--Shri Manoj Garbyal, 3rd Additional District Judge, Dehradun, is hereby sanctioned medical leave for 17 days w.e.f. 17.04.2021 to 03.05.2021.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2021 ई0 (कार्तिक 29, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

IN my High School Marksheet and Aadhar card my name Sapna Correctly mentioned But due to some mistake in voter list my name Jyoti wrongly mentioned. In future I may be known as Sapna W/o Vipin Kumar.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Sapna W/o Vipin Kumar
Village Mundakhera Kalan,
Tehsil Lakshar (Haridwar)

सूचना

I changed my name from C. Lalitha to Lalitha Krishnaswamy after marriage. In future I may be known as Lalitha Krishnaswamy wife of Late P.Krishnaswamy, NDS school Shyampur, Rishikesh, Dehradun, Uttarakhand 249204

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Lalitha Krishnaswamy
W/o Late P.Krishnaswamy,
NDS school Shyampur, Rishikesh,
Dehradun, Uttarakhand 249204